International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 14-12-2024, Accepted: 13-01-2025, Published: 28-01-2025
Volume 11, Issue 1, 2025, Page No. 28-30

पश्चिमी राजस्थान में जाट समुदाय में राजनीतिक चेतना

प्रकाश चौधरी
इतिहास विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राज्यस्थान, भारत

सारांश
पश्चिमी राजस्थान में जाट समुदाय की राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति एक महत्वपूर्ण सामाजिक–विज्ञानिक अध्ययन का विषय है। यह समुदाय न केवल अपनी कृषि पर आधारित जीवनशैली के लिए जाना जाता है, बल्कि राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी ने उन्हें समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है।पश्चिमी राजस्थान में जाट समुदाय की उत्पत्ति और विकास का इतिहास समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कई साम्राज्यों और राजवंशों का केंद्र रहा है, जिन्होंने यहाँ के सामाजिक ढांचे पर गहरा प्रभाव डाला है। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास जाट में समुदाय की उत्पत्ति पर विभिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जाटों का संबंध आर्यों से है, जो प्राचीन काल में भारत में आए थे। अन्य सिद्धांतों के अनुसार, जाट एक स्थानीय जातीय समूह हैं जिन्होंने समय के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया है[1] मध्यकाल में, विशेष रूप से मुगल काल में, जाटों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए कई संघर्ष किए। महाराणा सूरजमल जैसे प्रमुख नेताओं ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया और अपनी स्वतंत्र रियासतें स्थापित कीं। इस संघर्ष ने जाट समुदाय को एकजुट किया और उनकी सामाजिक संरचना को मजबूत किया[2] ब्रिटिश शासन के दौरान, जाट समुदाय ने राजनीतिक जागरूकता विकसित की। इस अवधि में जाट महासभा जैसे संगठनों की स्थापना हुई, जिन्होंने राजनीतिक संगठन को बढ़ावा दिया और सामाजिक सुधारों के लिए कार्य किया। ब्रिटिश नीति के खिलाफ जाटों ने कई आंदोलनों में भाग लिया, जिससे उनकी राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि हुई[3] पश्चिमी राजस्थान में जाट समुदाय की राजनीतिक सक्रियता उनकी सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक संघर्षों से प्रेरित है। यह समुदाय राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कई प्रमुख राजनीतिक पदों पर आसीन है।

मूलशब्दः राजनीति, समाज, मुख्यमंत्री, भूमिका, लोकतांत्रिक, पश्चिम राजस्थान, कांग्रेस, भाजपा,महापंचायत, लोकदल

जाट समुदाय ने पश्चिमी राजस्थान में कई राजनीतिक नेताओं का उदय किया है, जिन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। इन नेताओं ने न केवल समुदाय के हितों की रक्षा की, बल्कि राज्य के विकास में भी योगदान दिया है[4] जाट समुदाय का राजनीति में सक्रिय भागीदारी कांग्रेस, भाजपा, और अन्य क्षेत्रीय दलों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह समुदाय विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन बनाकर अपने सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करता है[5] पश्चिमी राजस्थान में जाट समुदाय को कई चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं। जाट समुदाय ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग की है। इस मांग के पीछे उनका उद्देश्य समुदाय के युवाओं को अधिक अवसर प्रदान करना है। हालांकि, यह मांग विवादास्पद रही है और कई बार सामाजिक अस्थिरता का कारण बनी है[6] राजस्थान के कुछ हिस्सों में जातीय संघर्ष जाट समुदाय के साथ हुआ है, जिससे उनकी राजनीतिक सक्रियता में बाधा आई है। ये संघर्ष सामाजिक असमानता और राजनीतिक दबाव के कारण उत्पन्न होते हैं[7] पश्चिमी राजस्थान में जाट समुदाय की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रगति के साथ, उनके भविष्य में और भी संभावनाएँ हैं। शिक्षा, युवा नेतृत्व, और आधुनिक राजनीति में उनकी भागीदारी से यह समुदाय और भी सशक्त बन सकता है।शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और युवाओं के नेतृत्व से जाट समुदाय की राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिका और मजबूत हो सकती है। युवा नेता नए विचारों और नीतियों के माध्यम से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं[8]

राजनितिक दलों में जाट– भारत मे लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होने के बाद से ही राजस्थान स्तर पर कांग्रेस पार्टी के अलावा लोकदल व माकपा में जाट नेतृत्व काफी मजबूत रहा है।पिछले एक दशक तक काफी मजबूत जाट नेतृत्व रहने के बाद अब अन्य दलो के साथ साथ कांग्रेस में भी मजबूत जाट नेतृत्व का अभाव होता जा रहा है। इसी कारण प्रदेश की राजनीति मे जाटों की आवाज़ का असर अब ख़तम होता जा रहा है।राजस्थान कांग्रेस में सरदार हरलाल सिंह, चौधरी रामनारायण, परसराम मदेरणा, डा.चंद्रभान सिंह, चोधरी नारायण सिंह जैसे जाट नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे है।जबकि अलग अलग समय मे नाथूराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, रामदेव सिहं महरिया, कुम्भाराम आर्य, शीशराम ओला, डा.कमला बेनीवाल, सुमित्रा सिंह, कर्नल सोनाराम जैसे अनेक जाट बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले जनप्रिय नेता रह चुके है।राजस्थान की जाट बिरादरी को वैसे तो कांग्रेस का परम्परागत मतदाता माना जाता है। लेकिन पहले हरिदेव जौशी व रामनिवास मिर्धा के विधायक दल के नेता पद चुनाव मे मिर्धा की हार एवं फिर 1998 मे बहुमत आने के बावजूद सम्भावित मुख्यमंत्री चेहरा परसराम मदेरणा की जगह अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो मानो जाट मतदाताओं मे कांग्रेस के प्रति एक खरास का भाव पनप आया।जिस खारेपन का अहसास रुक रुक कर जाट बिरादरी मे आज भी कांग्रेस के प्रति देखा जा रहा है। प्रमुख रूप से जोधपुर, अजमेर, जयपुर व बीकानेर सम्भाग मे राजनीतिक दबदबा रखने वाली जाट बीरादरी की शूरुआती राजनीति की चमक–धमक सिद्धांत की मजबूत लकीर की तरह सभी तरह के मतदाताओं को साथ लेकर चलने मे महत्वपूर्ण नेतृत्व देने मे सक्षम थी।विभिन्न राजनीतिक दलो की कुटिल चाल व कमजोर जाट नेतृत्व के उभरने के कारण आज जाट राजनीति के यह हालात बने है।लोकदल के समय कांग्रेस की राजनीति को बैलेंस किये रखने मे जाट नेताओं का प्रदेश की राजनीति मे खासा दखल था। लोकदल के खातमे के बाद भाजपा मे जाट नेताओं का प्रवेश हुआ ओर भाजपा सरकार मे

राजस्थान व केंद्र सरकार मे जाट मंत्री भी बने।लेकिन कांग्रेस मे जो जाट नेताओं का दबदबा हुआ करता था वो भाजपा मे नहीं पनप पाया ओर नाही आगे जाकर पनपने की उम्मीद है।शेक्षणिक तौर पर पुराने जाट नेता नाथूराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, परशराम मदेरणा, रामदेव सिह महरिया, सुमित्रा सिंह व डा. कमला सहित सभी उस मुश्किल हालात मे भी काफी मजबूत थे।लेकिन पिछले कुछ सालो मे जाट नेताओं की एक नये रुप मे खेप आई है। उन नेताओं की शैक्षणिक योग्यताओं का पैमाना अलग नजर आता है।पूराने जाट नेता शैक्षणिक तौर पर मजबूत होने के बावजूद खेत व गावं के साथ साथ आमजन से काफी हद तक जूड़े हुये होने के अलावा अपने सिंद्धातों पर हर हाल मे अड़िग रहने वाले थे।कुल मिलाकर यह है कि राजस्थान मे कांग्रेस को मजबूती देकर पुरानी वाली दमदार व असरकारक स्थिति मे लाने के लिए कांग्रेस के थिंकटैंक को कांग्रेस के परम्परागत मतदाता दलित–मुस्लिम के साथ जाट मतदाताओं को जोड़ने के उपाय तलाशने होगे।उक्त तीनो मतदाताओं का गठजोड़ फिर से होकर अगर कांग्रेस की तरफ झुकाव हो जाता है तो फिर अन्य मतदाताओं का झुकाव भी कांग्रेस की तरफ खींचा चला आयेगा।दूसरी तरफ जाट बीरादरी को सोचना होगा कि उनका राजनीतिक नेतृत्व पहले के मुकाबले कमजोर व बैअसर क्यो होता जा रहा है। जबकि बीरादरी की शेक्षणिक व राजनीतिक चेतना मे पहले के मुकाबले काफी बदलाव आना माना जा रहा है।[9]

राजस्थान की राजनीति पर जाट समाज– राजस्थान में चुनाव से पहले जातिगत सियासत से वोटों के ध्रुवीकरण के लिए महापंचायतों का आयोजन होता रहा है। लेकिन जाट फैक्टर की बात करें तो 12 से 14 फीसदी वोट बैंक वाला जाट समाज अपनी एकजुटता के चलते सभी दलों पर भारी पड़ता है। ऐसा माना जाता रहा है कि समाज चुनावी समीकरणों को ताक पर रख एक साथ एक जगह वोट डालता है। जाट बाहुल सीटों पर सबसे बड़ा निर्णायक साबित होता है जाट फैक्टर।राजस्थान का शेखावटी इलाका जाट बाहुल है। लेकिन सीकर, झुंझुनूं, नागौर के साथ जोधपुर क्षेत्र में जाट समाज का पॉलिटिक्स में बड़ा दखल रहा है। जबकि प्रदेश के जयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, टोंक और अजमेर जिलों में भी जाट समाज चुनावी समीकरण बनाने और बिगाड़ने का दम रखता है।[10] राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 142 सीट सामान्य, 33 सीट अनुसूचित जाति और 25 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। लेकिन दलगत टिकट बंटवारें में सामान्य वर्ग में जहां राजपूत कैंडिडेट्स को सर्वाधिक टिकट मिलते हैं। वहीं ओबीसी में सबसे ज्यादा टिकट जाटों को बांटे जाते हैं राजस्थान की विधानसभा में 15 फीसदी से अधिक सीटों पर जाट समाज का कब्जा रहता है। राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ऐसा ही एक सवाल जाट समुदाय के भीतर तैरता रहता है. राजस्थान में सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी जाट समुदाय से अब तक कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सका. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों से जाट समुदाय के नेताओं के नाम तो कई बार उछले, लेकिन ऐन वक्त पर इन नामों पर विचार छोड़ दिया गया. हालांकि, दोनों ही दल जाट समुदाय के नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करते रहे हैं, लेकिन बात जब मुख्यमंत्री की आती है तो इस समुदाय के हाथ खाली रह जाते हैं. जानते हैं कि कब–कब ऐसा पल आया जब लगा कि जाट मुख्यमंत्री राजस्थान में बन सकता है और कैसे अंतिम दौर में निर्णय बदल दिया गया

प्रमुख जाट नेता– साल 1973 में रामनिवास मिर्धा मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे. उन्होंने इस पद के लिए सीधी लड़ाई भी लड़ी थी, लेकिन पार्टी की अंदरूनी वोटिंग में वो एक मत से हार गए थे. साथ ही कई जाट विधायकों ने भी उनका विरोध किया था, जिसके कारण वो सीएम नहीं बन सके थे. इसके बाद साल 1998 में परसराम मदेरणा मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे रहे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने एक लाइन का प्रस्ताव पास कर मुख्यमंत्री तय कर दिया और अशोक गहलोत सीएम चुने गए. आगे 2008 में कद्दावर जाट नेता शीशराम ओला ने भी अशोक गहलोत के सामने दावेदारी पेश की थी, लेकिन उन्हें विधायकों का समर्थन हासिल नहीं हुआ. इसके कारण वो सीएम नहीं बन सके जाट समाज के एक बड़े नेता कुंभाराम आर्य आपातकाल में करीब 17 माह जेल में रहे. ऐसे में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ तो वो कांग्रेस के सामने मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस की जीत की संभावना को देखते हुए वो कांग्रेस में शामिल हो गए. हालांकि, इस चुनाव में कांग्रेस हार गई. उस समय कांग्रेस के विरोध में चौधरी चरण सिंह का बड़ा प्रभाव था और वे कुंभाराम को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनके गलत निर्णय के कारण को सीएम बनते बनते रह गए जनता पार्टी की सरकार में इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कद्दावर जाट नेता रामनारायण चौधरी ने राजस्थान में पहली गिरफ्तारी देकर आलाकमान की नजर में आए थे. ऐसे में साल 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना गया. कांग्रेस की प्रचंड लहर थी, लेकिन लगातार तीन बार के विधायक रहे रामनारायण चौधरी खुद चुनाव हार गए. इस तरह से वो सीएम की रेस से बाहर हो गए-

राजनितिक दलों में जाट नेता– जाट समाज से कांग्रेस में सरदार हरलाल सिंह, परसराम मदेरणा, रामनारायण चौधरी, डॉ. चन्द्रभान, नाथूराम मिर्धा, नारायण सिंह राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं. वहीं, यदि भाजपा की बात की जाए तो यहां सतीश पूनियां पहले जाट अध्यक्ष बने थे, लेकिन इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री पद तक पहुंच नहीं सका. सतीश पूनियां को तो साढ़े तीन साल अध्यक्ष रहने के बाद ऐन चुनाव के वक्त प्रदेश अध्यक्ष से विदाई दे दी गई. कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी इसी समुदाय से आते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज से सतीश पुनिया को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी और समाज का एक धड़ा राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी देने लग गया। जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति है वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे एवं उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए। राजनीतिक रूप से किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा जिसके कारण जाट समाज पार्टी से खफा दिखा। साल 1931 में जातिगत जनगणना अंतिम बार हुई थी और इसमें अधिकृत रूप से राजस्थान की कुल जनसंख्या 1 करोड़ 17 लाख 86 हजार 04 थी. 1931 की जातिगत जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक जाट सबसे अधिक 10.72 लाख थे. ऐसे में थोड़ी बहुत जनंसख्या कम या अधिक हुई होगी. बावजूद इसके निसंदेह यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक आबादी जाटों की है. ये करीब 10 प्रतिशत के आसपास हैं. इनके इर्द–गिर्द कोई अन्य जाति नहीं है. वहीं, दूसरे स्थान पर ब्राह्मण समुदाय है. राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान में सामान्यतरू कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर रहती हैं. इसमें हमने शेखावाटी, मारवाड़ सहित राजस्थान की जाट बाहुल्य सीटों का विश्लेषण किया तो पाया कि ये वर्ग राजनीतिक रूप से बेहद सजग है. यदि एक पार्टी जाट को टिकट देती है और दूसरा अन्य वर्ग के प्रत्याशी पर भरोसा जताती है तो ऐसे में जाट मतदाता लामबंद होकर जाट उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं. इस लामबंदी से बचने के लिए करीब 30 से 40 सीटों पर दोनों ही पार्टियां

जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारती रही हैं. इसे सियासी पार्टियों की मजबूरी भी कह सकते हैं राजस्थान विधानसभा में पहुंचने वाले विधायकों की बात की जाए तो भी सबसे अधिक जाट समुदाय के ही विधायक चुने जाते रहे हैं. आकंड़ों के अनुसार हर विधानसभा क्षेत्रों में सभी दलों को मिलाकर करीब 30 से 40 विधायक चुन कर विधानसभा पहुंचते हैं. यह ज्यादातर शेखावाटी, बीकाणा, मारवाड़ व जयपुर के आसपास के जिलों से चुन कर आते हैं. इन क्षेत्रों में जाट जाति सामाजिक व आर्थिक रूप से प्रभावी है, इसलिए अन्य जाति के मतदाताओं को अपने पक्ष में प्रभावित करते हैं. वहीं, विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान के पुराने जिलों के हिसाब से 10 जिलों की लगभग 65 सीटों पर जाट मतदाताओं का सीधा असर है. साथ ही करीब 100 सीटों पर ये निर्णायक की भूमिका निभाते रहे हैं11रेगिस्तान में अपने लोक देवता तेजाजी के गीत गाते जाट समुदाय ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए लम्बी यात्रा की है. उनके हाथों में बंजर धरती को हरा–भरा करने का हुनर है.पहले वे महज खेत खलिहानों तक महदूद थे, मगर अब वे जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी की कहानियां लिख रहे हैं

विधानसभा की अध्यक्ष रही सुमित्रा सिंह कहती हैं, ''जाट का मतलब जस्टिस, एक्शन और ट्रुथ होता है. जो सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करे वो जाट है.

सुमित्रा सिंह की परवरिश स्वाधीनता सेनानी परिवार में हुई. उनके पिता जंग–ए–आज़ादी के सिपाही थे. वो कहती हैं, ''कांग्रेस और बीजेपी, दोनों पार्टियों ने इस समुदाय को सौगाते दी हैं.''

''कांग्रेस ने किसान वर्ग को 1952 में बड़ी सौगात दी. उस वक़्त मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने जमीन जोतने वाले काश्तकार को उसका मालिक बना दिया. फिर बीजेपी के कद्दावर नेता रहे स्व. भैरो सिंह शेखावत ने बारानी जमीन का लगान माफ़ कर बड़ा काम किया.''[12]

राजनीतिक दृष्टि से, जाट समुदाय का प्रभाव हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अत्यधिक है, जहाँ वे बड़ी संख्या में निवास करते हैं[13]। इन राज्यों में उनकी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा होने के कारण, वे राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं और विधानसभा एवं भारतीय संसद में महत्वपूर्ण पदों पर निर्वाचित होते हैं। चौधरी चरण सिंह जैसे प्रमुख जाट नेता, जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने, ने किसानों के अधिकारों, ग्रामीण विकास और कृषि सुधारों के लिए नीतियाँ बनाई और इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया[14]। वर्तमान समय में भी जाट नेता कृषि नीति, जल संसाधन संरक्षण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में अग्रणी भूमिका निभाते हैं।

जाट नेताओं का राजनीति में अक्सर ''किंगमेकर'' के रूप में प्रभाव होता है, जहाँ उनके समर्थन से गठबंधन सरकारें बनती हैं। इससे जाट नेताओं को अपनी समुदाय के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का अवसर मिलता है।[15]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, के. एस. (1994). People of India: Rajasthan-Anthropological Survey of India. ओक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
2. बायली, सुज़ैन. (2001). Caste- Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस
3. हबीब, इरफान. (1963). "The Agrarian System of Mughal India"- Oxford University Press
4. पुरी, बी. एन. (2008). History of the Jats and Their Role in Indian Politics. राधा पब्लिकेशंस.
5. देसवाल, एस. (2010). Education and Social Change among Jats in Haryana", International Journal of Social Research-
6. जाट महासभा के दस्तावेज़, Journal of Indian Social Movements, वॉल्यूम 15, संख्या 2.
7. राजस्थान पुलिस रिपोर्ट्स, Rajasthan Police Department Archives, 2019.
8. शर्मा, आर. (2020). Youth Leadership in Rajasthan-जयपुरः राजस्थान पब्लिशिंग हाउस
9. https://janamanas.com/congress-jat-politics-rajasthan/
10. https://navbharattimes.indiatimes.com/state/rajasthan/jaipur/jat-politics-in-rajasthan-know-all-about-jat-samaj-and-rajasthan-vidhansabha-2023/articleshow/99204807.cms
11. https://www.etvbharat.com/hindi/rajasthan/state/jhunjhnu/rajasthan-assembly-elections-2023-seven-decades-of-jat-politics-in-rajasthan-yet-no-leader-from-the-jat-community-has-become-chief-minister/rj20231130153547628628817
12. https://www.bbc.com/hindi/india-46386823
13. सिंह, आर. (2002). उत्तर भारत में जाटों का राजनीतिक प्रभाव'. नई दिल्लीः इंडियन पॉलिटिकल स्टडीज।
14. चौधरी, एस. (2014). चौधरी चरण सिंह का जीवन और विरासत. लखनऊरू यूपी ऐतिहासिक सोसाइटी।
15. मेहता, डी. (2003). किंगमेकर्सः भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय समुदायों की भूमिका. मुंबईः ग्लोबल पॉलिटिक्स पब्लिकेशन्स।